

भारत

का

विभाजन

स्मृतियाँ, पीड़ा और जिजीविषा

14
अगस्त
1947

भारत का विभाजन

रक्त से रची गई एक लकीर

वह विभाजन जिसने उपमहाद्वीप का नक्शा बदल दिया

1947 में भारत का बँटवारा सिर्फ़ एक नई सीमा रेखा खींचने से कहीं ज़्यादा था।

यह इतिहास में ज़बरदस्ती किए गए सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक विस्थापनों में से एक था, जिसने पंजाब, बंगाल, सिंध, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और कई अन्य इलाकों में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी।

सदियों के साझे इतिहास से फले-फूले शहर, कस्बे और गाँव अचानक बँट गए, जिससे परिवार अलग हो गए, समुदाय उजड़ गए और जानी-पहचानी जगहें हमेशा के लिए बदल गईं।

दर्द भरा पलायन

करीब 60 लाख गैर-मुस्लिम उस क्षेत्र से निकलने के लिए मजबूर हो गए, जिसे बाद में पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया। वहीं, लगभग 65 लाख मुस्लिम पंजाब, दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों से पश्चिमी पाकिस्तान चले गए। भारत के पूर्वी हिस्से में भी विस्थापन का यही सिलसिला चला। अनुमान है कि करीब 20 लाख गैर-मुस्लिम पूर्वी बंगाल (अब बांग्लादेश) से निकले, और 1950 के आसपास 20 लाख और पश्चिम बंगाल में शरण लेने पहुंचे। उसी दौरान, लगभग 10 लाख मुस्लिम पश्चिम बंगाल से पलायन कर गए। इस पूरे दौर में मारे गए लोगों की संख्या का अनुमान 5 लाख से लेकर 10 लाख या उससे अधिक तक जाता है।



विभाजन से पहले का भारत

बदलता हुआ राजनीतिक परिदृश्य (1905-1919)

एक अहम मोड़

बीसवीं सदी की शुरुआत भारत के संवैधानिक इतिहास में एक अहम मोड़ साबित हुई। बंगाल के विभाजन (1905) ने बड़े पैमाने पर राजनीतिक लामबंदी को जन्म दिया और शासन, प्रतिनिधित्व तथा भारत के राजनीतिक भविष्य पर सार्वजनिक बहस को तेज़ कर दिया।

राजनीति में नई आवाज़ों का उदय

ऑल-इंडिया मुस्लिम लीग (1906) के गठन ने संगठित राजनीतिक प्रतिनिधित्व में एक नया आयाम जोड़ा। जैसे-जैसे राजनीतिक भागीदारी बढ़ी, विभिन्न संगठनों ने भारत के संवैधानिक भविष्य के लिए अपनी-अपनी सोच को और अधिक स्पष्ट रूप से सामने रखा।

प्रतिनिधित्व का बदलता स्वरूप

इंडियन काउंसिल एक्ट (1909) ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों (Separate Electorates) की व्यवस्था की, जिससे धार्मिक पहचान के आधार पर अलग-अलग चुनावी क्षेत्र बने। ब्रिटिश शासन के तहत प्रतिनिधि सरकार के विकसित होते ढांचे में यह एक बड़ा बदलाव था।

सुधार तथा प्रतिनिधित्व

बाद के संवैधानिक सुधारों ने विधान परिषदों का विस्तार किया एवं राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाया। इन उपायों ने अधिक संख्या में भारतीयों को राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ा। इसी के साथ-साथ इन उपायों ने प्रतिनिधित्व, शासन और संविधान के संरक्षण पर होने वाली बहसों को भी नया रूप दिया।

एक नया संवैधानिक दौर

इन घटनाक्रमों ने भारत की संवैधानिक यात्रा को बदल दिया। जैसे-जैसे प्रतिनिधि राजनीति का विकास हुआ, पहचान, सत्ता-साझाकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल संवैधानिक चर्चा के केंद्र में आते गए-ये ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने आने वाले दशकों में भारत के भविष्य को आकार दिया।

विभाजन से पहले का भारत

गतिरोध और बढ़ता तनाव

(1946-1947)

अंतिम फ़ैसले की ओर

1947 की शुरुआत तक, मुख्य सवाल यह नहीं रह गया था कि सत्ता सौंपी जाएगी या नहीं, बल्कि यह हो गया कि सत्ता कैसे सौंपी जाएगी। ब्रिटेन ने जून 1948 तक सत्ता सौंपने का अपना इरादा ज़ाहिर किया। बातचीत के अंतिम चरण की देखरेख के लिए लॉर्ड लुइस माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत आए।



विभाजन से पहले का भारत

विभाजन का निर्णय (1947)

ब्रिटेन का फैसला

फ़रवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सत्ता को हस्तांतरित करने का अपना इरादा ज़ाहिर किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री **क्लेमेंट एटली** ने घोषणा की कि सत्ता **जून 1948** तक सौंप दी जाएगी। इस घोषणा के साथ ही भारत में ब्रिटिश शासन के आखिरी दौर की शुरुआत हुई।

माउंटबेटन योजना

आखिरी वायसराय **लॉर्ड लुइस माउंटबेटन** ने भारतीय राजनीतिक नेताओं के साथ गहन बातचीत की। **3 जून की योजना** में ब्रिटिश भारत के बंटवारे का प्रस्ताव रखा गया। इसमें **भारत** और **पाकिस्तान** नामक दो स्वतंत्र डोमिनियन बनाने की बात कही गई। मुख्य राजनीतिक दलों ने सत्ता हस्तांतरण के आधार के तौर पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

कानूनी मान्यता

'**भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947**' ने इस फैसले को कानूनी मान्यता दी। इस अधिनियम के तहत **15 अगस्त 1947** से **भारत** और **पाकिस्तान** डोमिनियन बने। इसने संप्रभुता सौंपने और ब्रिटिश भारत के बंटवारे के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया।

नई सीमाओं का निर्धारण

आज़ादी की तैयारियाँ तेज़ी से आगे बढ़ीं। नई अंतरराष्ट्रीय सीमा तय करने का **काम रेडक्लिफ़ बाउंड्री कमीशन** को सौंपा गया। **रेडक्लिफ़ अवॉर्ड** आज़ादी के बाद ही सार्वजनिक किया गया, जिससे लाखों लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहे कि वे किस देश का हिस्सा होंगे।



जून, 1947 - भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
ब्रिटिश भारत के इतिहास में दूसरी और आखिरी बार था, जब किसी
वायसराय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।

इसमें तीन सौ से अधिक पत्रकार मौजूद थे - अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप और
भारत के कोने-कोने से आए प्रतिनिधि, जो पूरी एकाग्रता से वायसराय की
घोषणा सुन रहे थे। इसे 'माउंटबेटन योजना' कहा गया जो औपचारिक तौर पर
भारत की आज़ादी और विभाजन दोनों के बारे में थी।

सत्ता हस्तांतरण की योजना को लगभग एक साल पहले
खींचते हुए माउंटबेटन ने 15 अगस्त का दिन इस काम के लिए तय किया।
उन्होंने विभाजन की रुपरेखा प्रस्तावित की, जिसमें पंजाब और बंगाल के बंटवारे पर
पत्रकारों ने सवाल उठाए।

इसमें सबसे अहम प्रश्न विभाजन से होने वाले पलायन के बारे में था-

**इस बंटवारे के कारण जिन लोगों को पलायन करने के लिए
मजबूर होना पड़ा, उनका क्या होगा?**

विभाजन से पहले का भारत

"वे खुद ही चले जाएंगे"

एक आसन्न त्रासदी

जब बंटवारे की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों के विस्थापन की संभावना के बारे में पूछा गया, तो माउंटबेटन ने ऐसा जवाब दिया जो इतिहास में खून की स्याही से लिखा गया:

"व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा नहीं लगता (कि लोगों का विस्थापन होगा)....
कुछ हद तक लोगों का आना-जाना स्वाभाविक रूप से होगा...
लोग खुद ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे।"
— द टिब्यून, 5 जून, 1947



For CARPETS and more

LARGEST AND BEST at any Price. Wholesale Prices in Northern, Southern, Eastern and Western India.

The Times of India

ESTABLISHED 1858

NO. 101, VOL. CXL BOMBAY, WEDNESDAY, JUNE 5, 1947 PRICE TWO ANNAS



SAHARA BAZAAR

WAY OUT OF INDIAN DEADLOCK

BRITAIN'S PLAN FOR SMOOTH TRANSFER OF POWER

Immediate Dominion Status Granted

PEOPLE ASKED TO DECIDE PARTITION QUESTION

Present Constituent Assembly Not Disturbed

THE BRITISH GOVERNMENT HAVE PROMISED IMMEDIATE DOMINION STATUS TO INDIA—THIS YEAR—AND THEIR PLAN BY WHICH THEY WILL END THEIR 80 YEARS OF RULE PUTS FULL RESPONSIBILITY FOR THE FUTURE OF INDEPENDENT INDIA WHOLLY ON THE SHOULDERS OF THE INDIAN PEOPLE, LEAVING THEM TO CHOOSE OF PARTITION OR MAKING OF THEIR DECISIONS FOR THEMSELVES ALONE.

Two-Fold Purpose

The two-fold purpose of the plan, which was announced simultaneously to the Indian people and in both Houses of Parliament on Tuesday, is (1) to make possible the maximum degree of harmony and co-operation among the Indians

Only Practical Method

PREMIER'S VIEW

Plan Commended To Commons

MR. NEHRU COMMENDS PLAN TO NATION

Mr. Jinnah Hopeful Of League's Acceptance

SARDAR BALDEV SINGH CALLS IT "SETTLEMENT"

MR. NEHRU, June 5

MR. JINNAH, June 5

MR. BALDEV SINGH, June 5



Lord Mountbatten

"UNIFIED INDIA BEST SOLUTION"

Viceroy's Appeal

"THERE IS INDIAN CONSENSUS"

NEW DELHI, June 5.

The Viceroy, Lord Mountbatten, today announced that the British Government had accepted the proposal that they should transfer power to the Indian people, in the form of a constituent assembly, on August 15, 1947.

जून 1947: अखबार में बंटवारे की घोषणा

भारत का विभाजन

रैडक्लिफ़ लाइन



एक विभाजित देश का नक्शा

सर सिरिल रैडक्लिफ़, जो एक ब्रिटिश वकील थे और जिन्होंने पहले कभी भारत में कदम नहीं रखा था, उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच नई सीमाएँ तय करने के लिए सिर्फ़ 40 दिन दिए गए थे।

समय की भारी कमी के बीच काम करते हुए, उन्होंने गाँवों का दौरा किए बिना, नदियों और जंगलों का अध्ययन किए बिना, या उस इलाके के लोगों को जोड़ने वाले आर्थिक और सामाजिक नेटवर्क को पूरी तरह समझे बिना ही प्रांतों, ज़िलों और समुदायों का बँटवारा कर दिया।

बंगाल में बँटवारा मुख्य रूप से धार्मिक आधार पर किया गया, जिसमें अक्सर लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक संबंधों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया। वहीं पंजाब में रैडक्लिफ़ लाइन के नतीजे और भी भयानक साबित हुए।

प्रांत के बँटवारे ने रातों-रात लाखों हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को अल्पसंख्यक बना दिया, जिससे आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे हिंसक जबरन विस्थापन शुरू हुआ।

सीमाएँ तो तय कर दी गई थीं, लेकिन बँटवारे के कारण लोगों के बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन को संभालने के लिए कोई व्यापक योजना नहीं थी।

जल्दबाज़ी में किए गए इस बँटवारे की मानवीय कीमत बहुत भयानक थी और यह आज भी सीमा के दोनों ओर लाखों लोगों की यादों में बसी हुई है। अपना काम पूरा करने के बाद रैडक्लिफ़ कभी भारत नहीं लौटे। कहा जाता है कि उनका मानना था कि भारत और पाकिस्तान, दोनों ही उन्हें उनके द्वारा तय की गई सीमा के कारण हुई तकलीफ़ों के लिए ज़िम्मेदार ठहराएँगे।



विभाजन के दौरान भारत

एक रक्तरंजित पलायन का आरम्भ

अनजाने सफ़र की शुरुआत

बंटवारे के ऐलान ने रातों-रात लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। जैसे ही भारत और पाकिस्तान की नई सीमाएँ बनीं, परिवार एक अनिश्चित सीमा के अलग-अलग तरफ़ हो गए। रेडक्लिफ़ लाइन ने पंजाब और बंगाल को बाँट दिया, जिससे गाँव, शहर और परिवार अलग-अलग हो गए। लाखों लोगों के सामने यह मुश्किल फ़ैसला था कि वे वहीं रहें या चले जाएँ। बहुत से लोग सिर्फ़ वही सामान लेकर निकले जिसे वे उठा सकते थे; उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे कभी वापस लौट पाएँगे या नहीं।



इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन

कुछ ही महीनों में, लोगों का एक अभूतपूर्व विस्थापन हुआ। अनुमान के मुताबिक, 1.4 से 1.8 करोड़ लोगों ने नई बनी सीमाओं को पार किया। हिंदू और सिख भारत की ओर चले गए, जबकि कई मुसलमान पाकिस्तान चले गए। इतने कम समय में इतनी बड़ी आबादी का विस्थापन पहले कभी नहीं हुआ था।

लाखों लोगों के लिए, घर बस एक याद बनकर रह गया

जिसे वे एक अनजान सीमा के पार ले गए...



भारत का विभाजन जब सरहदें खिंचीं, इंसान बिखर गए

उथल-पुथल में फंसा जनसमूह

इस पलायन के दौरान कई इलाकों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। कस्बों और गांवों में सांप्रदायिक टकराव हुए। इस अफरा-तफरी में परिवार बिछड़ गए। बहुत से लोगों ने अपने प्रियजनों, घरों और रोज़गार को खो दिया।

हमेशा के लिए बदल गई ज़िंदगियाँ

बंटवारे की मानवीय कीमत सिर्फ़ लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने तक ही सीमित नहीं थी। लाखों लोगों की जान चली गई; इतिहासकारों के अनुमान अलग-अलग हैं। अनगिनत महिलाओं और बच्चों ने बहुत मुश्किलों का सामना किया। पीढ़ियों तक नुकसान, बिछड़ने और अनिश्चितता की यादें बनी रहीं।



हर आंकड़े के पीछे एक परिवार,
एक घर और हमेशा के लिए बदल गई एक ज़िंदगी मौजूद थी...



विभाजन के दौरान भारत नई सरहदों के पार, विस्थापन की अंतहीन राह

उम्मीद और निराशा की ट्रेनें

रेलवे लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने का मुख्य ज़रिया बनीं। शरणार्थियों की ट्रेनों ने लाखों लोगों को नई सीमाओं के पार पहुँचाया। नई जगह बसने की कोशिश कर रहे बहुत से लोगों के लिए मालगाड़ियां भी जीवन-रेखा बन गईं। रेलवे स्टेशन आँसुओं, बिछड़न और अनिश्चित प्रतीक्षा के गवाह बन गए। कई यात्राएँ बहुत मुश्किलों और खतरों से भरी थीं।



चलते हुए लोगों के जत्थे

हर कोई ट्रेन से सफ़र नहीं कर रहा था। हज़ारों लोगों ने पैदल, बैलगाड़ी, साइकिल और ट्रक से सफ़र किया।

शरणार्थियों के लंबे जत्थे सड़कों और खेतों में मीलों तक फैले हुए थे। आज़ादी के बाद भी कई महीनों तक लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना जारी रहा।



हर सड़क, हर रेलपथ और हर कारवाँ अपने साथ साहस,
पीड़ा और जीवट की अनगिनत कहानियाँ लेकर चला...

विभाजन के दौरान भारत

विभाजन का सबसे गहरा आघात महिलाओं ने सहा

महिलाओं की नज़र से विभाजन

1947 में भारत के बंटवारे के दौरान महिलाओं को सांप्रदायिक हिंसा के सबसे भयानक रूपों का सामना करना पड़ा। हज़ारों महिलाओं का अपहरण किया गया, उनके साथ यौन हिंसा हुई, ज़बरदस्ती शादी कराई गई, उनकी तस्करी की गई या उन्हें उनके परिवारों से अलग कर दिया गया। अक्सर महिलाओं को समुदाय की इज़्ज़त का प्रतीक मानकर निशाना बनाया जाता था।



'रिकवरी ऑपरेशन'

हिंसा के बीच कई महिलाओं की जान चली गई या वे अपने प्रियजनों से बिछड़ गईं। बंटवारे के बाद, भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इतिहास के सबसे बड़े 'रिकवरी ऑपरेशन' (लोगों को वापस लाने के अभियान) में से एक को अंजाम दिया। 1947 और 1950 के दशक के मध्य के बीच, अगवा की गई 30,000 से ज़्यादा महिलाओं को आधिकारिक तौर पर वापस लाया गया और नई सीमा के पार उनके देश भेजा गया।

हिम्मत और नई शुरुआत

बचे हुए लोगों में से कई के लिए घर लौटना नई चुनौतियाँ लेकर आया, जिनमें सामाजिक बदनामी और परिवार द्वारा ठुकराया जाना शामिल था। फिर भी, अनगिनत महिलाओं ने असाधारण हिम्मत के साथ अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारा; वे शिक्षिका, नर्स, उद्यमी, कारीगर, समाज-सेविका और घर की मुखिया बनीं। उनकी हिम्मत और पक्के इरादे भारत के राष्ट्र-निर्माण की कहानी का एक अहम हिस्सा बन गए।



पंजाब का विभाजन

बँटी हुई धरती

पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब

रेडक्लिफ लाइन ने पंजाब के ऐतिहासिक प्रांत को पूर्वी पंजाब (भारत) और पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान) में बांट दिया। जो शहर लंबे समय से व्यापार, संस्कृति और आपसी रिश्तों से जुड़े थे, वे अचानक अलग हो गए। लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जबकि अमृतसर भारत का मुख्य सीमावर्ती शहर बनकर उभरा।

विस्थापन का केंद्र

बंटवारे के दौरान पंजाब में आबादी का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ। हिंदू और सिख लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, लायलपुर, शेखूपुरा, सियालकोट, गुजरांवाला और मोंटगोमरी छोड़कर भारत आ गए, जबकि मुसलमान अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, फिरोजपुर, होशियारपुर और पटियाला से पाकिस्तान चले गए।

सीमावर्ती इलाकों में हिंसा

रावलपिंडी, लाहौर, शेखूपुरा, गुजरांवाला, अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। गांवों को नष्ट कर दिया गया, शरणार्थियों के काफिलों पर हमले हुए और नई सीमा पार करने वाली ट्रेनें बंटवारे की दुखद निशानी बन गईं।

अमृतसर: आज़ादी और शरण का प्रवेश द्वार

नई सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर स्थित अमृतसर, पश्चिमी पंजाब से आने वाले हजारों लोगों के लिए पहली शरणस्थली बना। भारत के दूसरे हिस्सों में जाने से पहले, इसके रेलवे स्टेशन, शरणार्थी शिविरों, गुरुद्वारों और राहत रसोइयों ने अनगिनत विस्थापित परिवारों को आश्रय और मदद दी।

ANNEX III. 2.

15

	Area in sq.miles	Total Population	Muslims	Non-Muslims	Sikhs.
East Punjab	38535	15685593	6416244	9269749	2794522
" "	" "	- 3485279	- 3485279	- 846268	- 241025
		<u>12201414</u>	<u>2986403</u>	<u>10118011</u>	<u>2553507</u>
West Punjab	50520	12691599	9760034	2931565	973072
" "	" "	- 3485279	- 3485279	- 846268	- 241025
		<u>16475978</u>	<u>14081975</u>	<u>2085303</u>	<u>732047</u>

ANNEX IV.

16

Statement of non-muslims in dangerous zones of West Punjab
who require exchange with Muslims of East Punjab.

Name of District.	Non-muslims including Sikhs	Sikhs.
1. Rawalpindi	157038	64127
2. Mianwali	70061	6865
3. Gujrat	159343	70233
4. Shahpur	163008	48046
5. Jhelum	66625	24680
6. Attock	64747	20120
7. Muzaffargarh	98775	5882
8. D.G. Khan	68672	10725
Total	<u>846367</u>	<u>241025</u>

पंजाब का विभाजन

आसमानों में जीवन की डोर

इस पलायन के दौरान भारतीय वायु सेना ने भी
अहम भूमिका निभाई

सितंबर 1947 में पंजाब के ऊपर उड़ रहे विमानों ने एक चौकाने वाला
नज़ारा देखा: लगभग 30,000 शरणार्थी पैदल ही करीब 40 किलोमीटर का
रास्ता तय कर रहे थे।

इन विमानों ने देखा कि आगे कुछ हमलावर भीड़ घात लगाकर बैठी थी
और थके-हारे शरणार्थियों पर हमला करने की योजना बना रही थी।

विमानों ने तुरंत ज़मीन पर मौजूद सैन्य गश्ती दलों को
उनकी लोकेशन की जानकारी दी।



पंजाब का विभाजन

डेरावालों की कहानी

डेरावालों की धरती

डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान और मियांवाली से मिलकर बना डेराजाट इलाका, अविभाजित पंजाब का डेराजाट डिवीज़न था। यहाँ हिंदू और सिख समुदाय के लोग रहते थे जो व्यापार, प्रशासन, शिक्षा और अलग-अलग तरह के पेशों से जुड़े थे। पीढ़ियों से इन समुदायों ने इस इलाके की समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक ज़िंदगी में योगदान दिया।

विस्थापन और पलायन

बंटवारे के कारण ज़्यादातर हिंदू और सिख डेरावालों को पश्चिमी पंजाब में अपनी पुश्तैनी ज़मीन छोड़नी पड़ी। वे अपने घर, कारोबार, मंदिर, गुरुद्वारे और सदियों पुराने सामाजिक रिश्ते पीछे छोड़ आए और भारत में सुरक्षित जगह पहुँचने के लिए बेहद मुश्किल सफ़र तय किया।

नई ज़िंदगी की शुरुआत

कई डेरावाल परिवार दिल्ली, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, जयपुर और मुंबई में बस गए। विस्थापन के सदमे के बावजूद, उन्होंने डेरावाली भाषा, रीति-रिवाजों, खान-पान और सांस्कृतिक परंपराओं को बचाए रखते हुए अपनी ज़िंदगी को फिर से खड़ा किया।

एक स्थायी विरासत

डेरावाल शरणार्थियों ने व्यापार, कपड़ा उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, जन-सेवा और इंडस्ट्री में अहम योगदान दिया और आज़ादी के बाद के भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में बड़ी भूमिका निभाई।

संजो कर रखी गई पहचान

डेरावाल सभा जैसे सामाजिक संगठनों ने शरणार्थियों को फिर से बसने में मदद की, ज़रूरतमंद परिवारों का साथ दिया और यह सुनिश्चित किया कि डेरावाल समुदाय का इतिहास, परंपराएँ और सामूहिक यादें आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचती रहें।

पंजाब का विभाजन ग्रंथ में सँजोई घर की विरासत



**बंटवारे के समय डेरा इस्माइल खान से लाई गई
यह उर्दू में लिखी गई श्रीमद्भगवद्गीता अपने आप में एक
परिवार की आस्था और पूरे समुदाय की विरासत को संजोए हुए है**

श्रीमद्भगवद्गीता का यह पुराना उर्दू संस्करण एक अनमोल पारिवारिक धरोहर है, जिसे १९४७ के बंटवारे के दौरान श्रीमती टुटेजा के पिता डेरा इस्माइल खान से भारत लाए थे। यह केवल एक कीमती चीज़ नहीं, बल्कि पीछे छूटे वतन और परिवार की अटूट आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी एक जीवंत कड़ी है।

कभी रोज़ाना पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाली श्रीमद्भगवद्गीता की यह प्रति आज यादों की एक धरोहर के रूप में मौजूद है। यह उस परिवार, समुदाय और जीवन-शैली की कहानी को संजोए हुए है, जो उजड़ तो गई, लेकिन कभी भुलाई नहीं जा सकी।



पंजाब का विभाजन एक धुंधला सा रेखा-चित्र

डेरा इस्माइल खान की मुन्नी देवी

ये तस्वीरें उस परिवार की हैं जिसने 1947 के बंटवारे के दौरान डेरा इस्माइल खान से विस्थापित होने के बाद जयपुर में अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की। उन लाखों लोगों की तरह जिन्हें अपना पुश्तैनी घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था, यह परिवार भी अपने साथ न सिर्फ़ कुछ खास चीज़ें, बल्कि उस वतन की यादें भी ले आया जहाँ वे कभी वापस नहीं जा पाए। आज, ये तस्वीरें उनके विस्थापन, हिम्मत और नई शुरुआत के सफ़र की गवाह हैं।

इस सफ़र को तय करने वालों में स्वर्गीय श्री हीरा नंद भाटिया की बहन मुन्नी देवी भी शामिल थीं। बचपन में ही विधवा हो चुकीं मुन्नी देवी 37 साल की थीं जब बंटवारे ने उनकी ज़िंदगी को जड़ से उखाड़ कर रख दिया। वह अपने परिवार के साथ जयपुर चली गईं और 1985 में अपने निधन तक अपने भाई के साथ ही रहीं। उनकी ज़िंदगी उन अनगिनत महिलाओं की खामोश हिम्मत को दिखाती है जिनकी निजी कहानियाँ बंटवारे के बड़े इतिहास का अहम हिस्सा बन गईं।



इस तस्वीर में एक नक्काशीदार चांदी का आईना और कमरबंद दिखाया गया है, जो जयपुर के एक डेरावाल (भाटिया) परिवार की पुश्तैनी चीज़ें हैं। कमरबंद पर 19वीं सदी के "एक-आना" के सिक्के लगे हैं, जिन सभी पर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का नाम लिखा है।

बंगाल का विभाजन

बंगाल: एक धरती, दो दावेदारियाँ

बंगाल: जो बचा रहा, जो जुड़ा रहा

1940 के दशक में जब पाकिस्तान की मांग ज़ोर पकड़ने लगी, तो आज़ादी से पहले बंगाल का भविष्य सबसे विवादित मुद्दों में से एक बन गया। मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव दिया कि पूरा बंगाल या तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए या एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में उभरे; उनका तर्क था कि बंगाल की अर्थव्यवस्था और भूगोल के कारण इसका बंटवारा व्यावहारिक नहीं होगा।

कई नेताओं को डर था कि इससे कलकत्ता, जो पूर्वी भारत का औद्योगिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र था, वह भारतीय संघ से बाहर हो जाएगा। ऐसे अहम मोड़ पर, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिमी बंगाल के हिंदू-बहुल ज़िलों को भारत में ही बनाए रखने के सबसे बड़े पैरोकार बनकर उभरे। लगातार राजनीतिक बातचीत, जन-लामबंदी और संवैधानिक वकालत के ज़रिए उन्होंने तर्क दिया कि लाखों बंगालियों को उनकी लोकतांत्रिक इच्छा के विरुद्ध किसी राज्य में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।



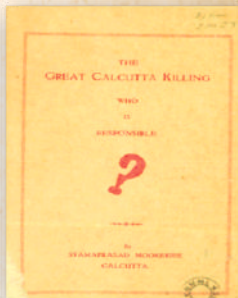
बंगाल का विभाजन

बंगाल में बंटवारे की समयरेखा-1

तारीख	घटना	महत्त्व
16 अक्टूबर 1905	लॉर्ड कर्ज़न द्वारा बंगाल का विभाजन	प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल को पूर्वी बंगाल और असम तथा पश्चिमी बंगाल में बाँट दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और राष्ट्रवादी भावनाएं प्रबल हुईं।
12 दिसंबर 1911	बंगाल विभाजन का रद्द होना	लगातार हो रहे जन-विरोध के बाद अंग्रेजों ने 1905 के बंटवारे को रद्द कर दिया। बंगाल को फिर से एक कर दिया गया, हालांकि बिहार, ओडिशा और असम अलग प्रांत बन गए।
23 मार्च 1940	लाहौर प्रस्ताव	मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र मुस्लिम-बहुल राज्यों की मांग की थी, जिसने पाकिस्तान की नींव रखी और बंगाल के भविष्य को लेकर सवाल खड़े किए।
29 जुलाई 1946	डायरेक्ट एक्शन की घोषणा	मुस्लिम लीग ने 'डायरेक्ट एक्शन' की घोषणा की।
16 अगस्त 1946	डायरेक्ट एक्शन डे	कलकत्ता में हुई सांप्रदायिक हिंसा में हज़ारों लोगों की जान गई और इसने बंगाल में हिंदू-मुस्लिम संबंधों को एक बेहद नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। 16-19 अगस्त 1946 का समय कलकत्ता के भीषण नरसंहार के तौर पर इतिहास में दर्ज है।

बंगाल का विभाजन

बंगाल में 'डायरेक्ट एक्शन डे' से जुड़ी घटनाओं के दौरान डॉ. श्यामा प्रसाद का नेतृत्व



हिंसा और अफ़रातफ़री का फैलना

16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के 'डायरेक्ट एक्शन डे' (प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस) ने चार दिनों तक सुनियोजित सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया।

एच.एस. सुहरावर्दी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की, जिससे भीड़ को लूटपाट, आगजनी और हत्या करने का मौका मिला, जबकि प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे "बेलगाम बर्बरता" करार दिया।

यह भयावहता जल्द ही नोआखाली तक फैल गई, जहाँ बड़े पैमाने पर हत्याएं, बलात्कार और जबरन धर्म-परिवर्तन की घटनाएं हुईं।

डॉ. श्यामा प्रसाद ने राहत कार्यों की अगुवाई की

सरकार की मिलीभगत और तंत्र के विफल हो जाने के बावजूद, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पीछे नहीं हटे। उन्होंने आगे बढ़कर ये कदम उठाए:

- हिंदुस्तान नेशनल गार्ड का गठन किया।
- बचाव, राहत और सुरक्षा कार्यों का नेतृत्व किया।
- दंगा-प्रभावित क्षेत्रों का व्यक्तिगत रूप से दौरा किया।
- नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) को संगठित और सक्रिय किया।

अक्टूबर-
नवंबर
1946

नोआखाली हिंसा

नोआखाली में व्यापक हिंसा और विस्थापन के बाद महात्मा गांधी ने प्रभावित गांवों का दौरा करके शांति का संदेश दिया।



बंगाल का विभाजन

बंगाल में बंटवारे की समयरेखा-2

तारीख	घटना	महत्त्व
2 मई 1947	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखा	मुखर्जी ने आग्रह किया कि यदि भारत का विभाजन होता है, तो बंगाल का भी विभाजन किया जाना चाहिए ताकि हिंदू-बहुल पश्चिमी जिले भारत के साथ ही रह सकें।
20 जून 1947	बंगाल विधानसभा मतदान	विधानसभा ने अलग-अलग मतदान किया। पश्चिमी बंगाल के सदस्यों ने विभाजन और भारत में शामिल होने का समर्थन किया, जबकि पूर्वी बंगाल ने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मतदान किया। यह बंगाल के विभाजन की दिशा में एक निर्णायक संवैधानिक कदम बन गया।
3 जून 1947	माउंटबेटन योजना की घोषणा	ब्रिटिश सरकार ने सत्ता के हस्तांतरण के आधार के रूप में विभाजन को स्वीकार किया, जिसमें बंगाल और पंजाब के विभाजन की संभावना भी शामिल थी।
15 अगस्त 1947	भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र देश बने	बंगाल को पश्चिम बंगाल (भारत) और पूर्वी बंगाल (पाकिस्तान) में विभाजित कर दिया गया था, हालाँकि सटीक सीमा की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई थी।
17 अगस्त 1947	रैडक्लिफ़ सीमा पुरस्कार प्रकाशित	स्वतंत्रता के दो दिन बाद अंतिम सीमा की घोषणा की गई। तब जाकर लाखों लोगों को यह ज्ञात हुआ कि उनके घर नई सीमा के किस हिस्से में आए हैं, जिसके बाद व्यापक स्तर पर प्रवास और विस्थापन शुरू हो गया।

रैडक्लिफ द्वारा खींची गई रेखा का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब और बंगाल पर पड़ा

बंगाल पहले से ही सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा था। 1946 के कलकत्ता दंगों ने पूरे भारत में सांप्रदायिक तनाव की नींव डाल दी थी। जो समुदाय सदियों से उपमहाद्वीप में सह-अस्तित्व की भावना के साथ रहते थे, वे अब विभाजित हो गए थे।

यह सब अंग्रेजों की "फूट डालो और राज करो" की नीति का हिस्सा था, जहाँ वे सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों को भड़काते थे।



विभाजन के बाद का भारत

संघर्ष से राष्ट्र-निर्माण तक

राहत और पुनर्वास (1947-1950)

- उत्तर और पूर्वी भारत में बड़े पैमाने पर शरणार्थी कैंप बनाए गए।
- लाखों लोगों को भोजन, रहने की जगह, स्वास्थ्य सेवाएँ और रोज़गार उपलब्ध कराए गए।
- दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और अन्य जगहों पर पुनर्वास कॉलोनियाँ बसाई गईं।
- विस्थापित परिवारों को फिर से बसाने में 'इवैक्यूई प्रॉपर्टी लॉ' (छोड़ी गई संपत्ति से जुड़े कानून) और ज़मीन के पुनर्वितरण ने मदद की।

ज़िंदगी को फिर से खड़ा करना

- शरणार्थियों ने खेती, व्यापार और उद्यमिता के ज़रिए अपनी आजीविका फिर से शुरू की।
- नए बाज़ार, उद्योग और शिक्षा संस्थान उभरे।
- समुदायों ने नए घरों में ढलते हुए भी अपनी परंपराओं को बनाए रखा।
- भारी सदमे के बावजूद, महिलाओं ने परिवारों और समुदायों को फिर से खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई।

हिम्मत और जज़्बे से राष्ट्र-निर्माण

- विस्थापित समुदायों ने भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में बड़ा योगदान दिया।
- उन्होंने दिल्ली, अमृतसर, लुधियाना, कोलकाता, जयपुर और फरीदाबाद जैसे शहरों का कायापलट कर दिया।
- शरणार्थी उद्यमी, शिक्षक, सरकारी अधिकारी, कलाकार, वैज्ञानिक और जन-नेता बने।
- उनकी हिम्मत और जज़्बे ने नए स्वतंत्र गणतंत्र को मज़बूत बनाया।

विभाजन के बाद का भारत

संघर्ष से राष्ट्र-निर्माण तक

राहत और पुनर्वास (1947-1950)

विभाजन के बाद पूरे भारत में कई बड़े शरणार्थी कैंप बनाए गए।

- **किम्सवे कैंप, दिल्ली** - भारत का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप, जहाँ 3,00,000 तक विस्थापित लोगों को आश्रय दिया गया। यह राहत, रजिस्ट्रेशन और पुनर्वास का एक मुख्य केंद्र बन गया।
- **पुराना किला, दिल्ली** - दिल्ली के सबसे शुरुआती और बड़े कैंपों में से एक। हज़ारों शरणार्थियों, खासकर पश्चिमी पंजाब से आए लोगों को इस ऐतिहासिक किले में अस्थायी आश्रय मिला।
- **हुमायूँ का मक़बरा कैंप, दिल्ली** - शुरुआत में इसका इस्तेमाल पाकिस्तान जाने का इंतज़ार कर रहे मुसलमानों को आश्रय देने के लिए किया गया और बाद में आबादी के आदान-प्रदान के दौरान राहत कार्यों के लिए।
- **कुरुक्षेत्र शरणार्थी कैंप, हरियाणा** - उत्तरी भारत के सबसे बड़े ट्रांज़िट कैंपों में से एक, जहाँ कभी-कभी लाखों शरणार्थी रहते थे। यह अपने व्यवस्थित राहत कार्यों के लिए जाना गया, जिसमें कम्युनिटी किचन, मेडिकल सेवाएँ और स्कूल शामिल थे।
- **अलवर और भरतपुर कैंप (राजस्थान)** - पश्चिमी पंजाब और सिंध से आने वाले शरणार्थियों को उनके स्थायी पुनर्वास से पहले रखने के लिए बनाए गए।
- **अमृतसर ट्रांज़िट कैंप (पंजाब)** - कैंपों का एक नेटवर्क जो अटारी-वाघा बॉर्डर पार करने वाले शरणार्थियों को आगे बढ़ने से पहले तुरंत राहत देता था।
- **जालंधर और लुधियाना कैंप (पंजाब)** - विस्थापित लोगों के लिए महत्वपूर्ण पुनर्वास केंद्र, जो बाद में पूर्वी पंजाब में बस गए।

विभाजन के बाद का भारत

पूर्वी भारत के शरणार्थी शिविर



**कूपर्स कैप,
रानाघाट**
(पश्चिम बंगाल)

{ 1950 में स्थापित, यह पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए सबसे बड़े कैपों में से एक बन गया और कई दशकों तक सक्रिय रहा।

**धुबुलिया कैप,
नादिया**
(पश्चिम बंगाल)

{ लगातार कई बार हुए पलायन के दौरान पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए यह एक बड़ा शिविर बना रहा।

**बोनगांव और
बागदा कैप**
(पश्चिम बंगाल)

{ भारत-पूर्वी पाकिस्तान सीमा के पास मुख्य रिसेप्शन और ट्रांजिट सेंटर

**दंडकारण्य पुनर्वास
परियोजना**
(1958 से)

{ यह विभाजन के ठीक बाद का कोई शरणार्थी शिविर नहीं था, फिर भी यह एक व्यापक पुनर्वास परियोजना थी, जिसने पूर्वी पाकिस्तान के हज़ारों परिवारों को आज के छत्तीसगढ़, ओडिशा और उससे सटे इलाकों में फिर से बसाया।

विभाजन के बाद भारत

फिर से बसती ज़िंदगियाँ

शरणार्थियों से राष्ट्र-निर्माता तक

बेहद मुश्किलों के बावजूद, लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की। शरणार्थी कैंपों ने उन्हें कुछ समय के लिए रहने की जगह दी। पूरे भारत में नई बस्तियाँ और शहर बने। परिवारों ने फिर से अपने घर, कारोबार और संस्थान स्थापित किए।

हिम्मत और नई शुरुआत

घर, रोज़गार और जानी-पहचानी जगहें खोने के बाद, लाखों लोगों ने नई ज़िंदगी शुरू की। कड़ी मेहनत और लगन से, विस्थापित समुदायों ने आधुनिक भारत के निर्माण में मदद की- उन्होंने कारोबार शुरू किए, शिक्षा और जन-सेवा को बेहतर बनाया, कला और साहित्य में योगदान दिया, और खेती व व्यापार को मज़बूत किया। उनकी हिम्मत ने व्यक्तिगत त्रासदी को राष्ट्र-निर्माण की एक स्थायी विरासत में बदल दिया।

विस्थापन से गुज़रते हुए एक

असाधारण जीवटता का जन्म हुआ

विभाजन के बाद भारत फिर से बसती ज़िंदगियाँ

शरणार्थियों से राष्ट्र-निर्माता तक

विभाजन के बाद, सरदार करतार सिंह और सरदारनी गुरजीत कौर का परिवार आगरा में बस गया, उन लाखों लोगों की तरह जिन्होंने अपने पैतृक स्थानों को छोड़कर एक नई जगह पर अपना जीवन शुरू किया।



This is to certify that Shri Kartar Singh son of S.Bhan Singh is a registered and benefited displaced person from West Pakistan having migrated to India from Montgomery now in West Pakistan.

Kartar Singh

Shri Kartar Singh
He is a displaced
person and now
living in India after
migration

S. H. Saini

16/10/66



विभाजन के बाद भारत

दीना नाथ और सेवा राम

एक रसीद से हुई नई शुरुआत

विभाजन से पहले दीना नाथ और सेवा राम ने झेलम में साइकिल ठीक करने की एक छोटी सी दुकान को एक ऐसे कामयाब बिज़नेस में बदल दिया था जो लंदन से साइकिलें मंगाता था।

जब सांप्रदायिक हिंसा के कारण उन्हें नए बने पाकिस्तान से भागना पड़ा, तो लूटपाट से बचने के लिए वे अपना घर, बिज़नेस और सामान वहीं छोड़ आए।

इस अफरातफरी के बीच दीना नाथ अपनी जेब में सिर्फ एक रसीद लेकर निकले थे, जो साइकिलों की एक ऐसी खेप की थी जिसका आना अभी बाकी था।

हालांकि उन्होंने बड़ी मेहनत से खड़ा किया अपना बिज़नेस खो दिया, लेकिन उनकी बिज़नेस करने की हिम्मत बनी रही। यह उन अनगिनत शरणार्थियों की हिम्मत की मिसाल है, जिन्होंने बंटवारे के बाद लगभग शून्य से अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की।

विभाजन के बाद भारत फिर से बसती ज़िंदगियाँ

शरणार्थियों से राष्ट्र-निर्माता तक

दस्का (जो अब पाकिस्तान में है) में जन्मे रौनक सिंह ने 1947 के बंटवारे के दौरान अपना घर और कारोबार खो दिया था। वे एक शरणार्थी के तौर पर भारत आए और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया।

मसाले की दुकान में कुछ समय तक काम करने के बाद, उन्होंने परिवार के गहने बेचकर पैसे जुटाए और स्टील इंडस्ट्री में आने से पहले ट्रेडिंग का काम शुरू किया। उन्होंने 'भारत स्टील ट्यूब्स लिमिटेड' की स्थापना की, जो भारत की प्रमुख स्टील पाइप बनाने वाली कंपनियों में से एक बनी। बाद में उन्होंने 'अपोलो टायर्स' की शुरुआत की, जो आज एक ग्लोबल टायर कंपनी है।

कारोबार के अलावा, उन्होंने 'मारुति उद्योग लिमिटेड' के पहले चेयरमैन के तौर पर काम किया और FICCI और ASSOCHAM जैसे प्रमुख इंडस्ट्री संगठनों का नेतृत्व करते हुए भारत के औद्योगिक विकास में अहम योगदान दिया।

एक विस्थापित शरणार्थी से भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक बनने तक की रौनक सिंह की यात्रा, विभाजन से बचे अनगिनत लोगों के साहस, उद्यमशीलता और राष्ट्र-निर्माण की भावना का प्रतीक है।



विभाजन के बाद भारत बाहरीसन्स का सफ़र

विस्थापन से किताबों की दुनिया तक

बाहरीसन्स बुकसेलर्स की कहानी मंडी बहाउद्दीन (जो अब पाकिस्तान में है) के मलकवाल से शुरू होती है, जहाँ 1947 में बंटवारे की हिंसा के कारण अपना घर-बार छोड़ने से पहले बाहरी परिवार रहता था। लाखों लोगों की तरह, वे भी भविष्य को लेकर अनिश्चितता के साथ दिल्ली आए और किंग्सवे कैंप की शरणार्थी बस्तियों में अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की।

युवा बलराज बाहरी मल्होत्रा ने अपने परिवार का पेट पालने के लिए हर तरह का काम किया - जैसे फाउंटेन पेन बेचना, ट्रेनों में काम करना और सरकारी प्रकाशन बांटना। लेकिन किताबों के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ।

1953 में, उन्होंने खान मार्केट में एक छोटी सी किताबों की दुकान खोली, क्योंकि उनका मानना था कि किताबें मुश्किल समय में भी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। दुकान के लिए पैसे जुटाने के लिए उनकी पत्नी, भाग मल्होत्रा ने अपनी सोने की चूड़ियाँ बेच दीं। समय के साथ, बाहरीसन्स दिल्ली के सबसे पसंदीदा इंडिपेंडेंट बुकस्टोर्स में से एक बन गया। आज यह शहर भर में फल-फूल रहा है और परिवार की अगली पीढ़ी इसे चला रही है। यह दुकान हिम्मत, उम्मीद और ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली ताकत की मिसाल है।



विभाजन के बाद भारत विभाजन को स्मरण करते हुए

अधिसूचना

विभाजन की स्मृतियाँ पीढ़ियों तक जीवित रहती आई हैं। मौखिक इतिहास, संग्रहालय, स्मारक, साहित्य, फिल्में और अभिलेखागार इन अनुभवों को संजोकर रखते हैं।



2021 में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में अधिसूचित किया, ताकि भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान भारत के लोगों द्वारा सहे गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाई जा सके,

"देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है।"

श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

